सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई-2021 | अंक-03

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंधन निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंधन संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई-2021 | अंक-03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंधन निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंधन संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधारी
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्णा कुमार ➢ कृष्णाकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

विषय सूची

- सप्ताह के प्रमुख मुद्दे 1-13
- सप्ताह के चर्चित व्यक्ति 14-17
- सप्ताह के चर्चित स्थान 18-21
- सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22-27
- ब्रेन बूस्टर 28-35
- स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) 36-40
- स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न) 41-42

ध्येयIAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

Our other initiatives

UDAAN TIMES
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपियाँ
- चीन की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर पर
- मेक्सिको में मिली 'बातूनी' डायनासोर की नई नस्ल

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311
- लॉक डाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी
- निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22
- ताउते चक्रवात
- बीमा बांस
- तियानवेन-1
- स्किंक की नई प्रजाति
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
- रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपियाँ

चर्चा का कारण

- हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि अगले वर्ष तक पवित्र मंगोलियाई कंजुर (प्रत्येक 108 खंड) के लगभग 100 सेटों का पुनःमुद्रण कार्य पूरा करने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) वर्ष 2023 तक जारी रहेंगे।
- पांडुलिपियों में प्रतिस्थापित (enshrined) ज्ञान को शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं बड़े पैमाने पर आम लोगों तक प्रसारित करने हेतु दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना उद्देश्य है।

प्रमुख बिन्दु

- समाजवादी अवधि के दौरान काष्ठ चित्रों को जला दिया गया था और मठ अपने पवित्र ग्रंथों से वंचित हो गए थे। 1956-58 के दौरान, प्रोफेसर रघु वीरा ने दुर्लभ कंजुर पांडुलिपियों की एक माइक्रोफिल्म प्रति प्राप्त की और उसे भारत लेकर आ गए और 108 अंकों में मंगोलियाई कंजुर भारत में 1970 के दशक में राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रो. लोकेश चंद्रा द्वारा प्रकाशित किया गया।
- अब वर्तमान संस्करण का प्रकाशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक अंक में कंटेंट की एक सूची है जो मंगोलियाई में सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करती है।

मंगोलियाई कंजूर (Mongolian Kanjur) क्या है?

- 108 अंकों का बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ मंगोलियाई कंजुर मंगोलिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ माना जाता है। मंगोलियाई भाषा में 'कंजुर' का अर्थ होता है 'संक्षिप्त आदेश' जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द हैं।
- मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इसका काफी सम्मान किया जाता है तथा वे मंदिरों में कंजुर की पूजा करते हैं तथा एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपने प्रतिदिन के जीवन में कंजुर की पंक्तियों का पाठ करते हैं।
- मंगोलिया में लगभग प्रत्येक बौद्ध मठ में कंजुर को रखा जाता है। मंगोलियाई कंजुर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। कंजुर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है। मंगोलियाई कंजुर मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान उपलब्ध कराने का स्रोत है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

- भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रसार करने के अधिदेश (mandate) के साथ लांच किया गया था।
- पाण्डुलिपि (Manuscripts) कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते अथवा किसी अन्य सामग्री पर कम से कम 75 वर्ष पहले हस्त लिखित संयोजन को कहते हैं जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अथवा सौंदर्यपरक महत्त्व हो।
- लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पाण्डुलिपियों में नहीं आते। पाण्डुलिपियां सहस्त्र विभिन्न भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं। अक्सर एक भाषा विभिन्न लिपियों में लिखी होती है। उदाहरण के लिए संस्कृत उड़िया लिपि, ग्रंथ लिपि, देवनागरी लिपि और कई अन्य लिपियों में लिखी जाती है।
- पाण्डुलिपियां ऐतिहासिक रिकॉर्डों जैसे शिलालेखों, फरमानों, राजस्व अभिलेखों से भिन्न होती हैं जो इतिहास में घटनाओं अथवा प्रक्रियाओं के संबंध में सीधी सूचना प्रदान करते हैं। पाण्डुलिपियों में ज्ञान निहित होता है।

भारत और मंगोलिया के बीच संबंध

- भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक परस्पर संबंध सदियों पुराने हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा आरंभिक ईस्वी के दौरान ले जाया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप, आज मंगोलिया में बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक प्रभुत्व है। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। तब से, दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध एक नई ऊंचाई तक पहुंच गए हैं।
- अब भारत सरकार द्वारा मंगोलियाई सरकार के लिए मंगोलियाई कंजुर का प्रकाशन भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक सिम्फनी के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा तथा आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को और आगे ले जाने में योगदान देगा।

2. चीन की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर पर

चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन ने जनगणना के सरकारी आंकड़े जारी किये हैं। इस जनगणना के अनुसार बीते दशकों में चीन की आबादी सबसे धीमी गति से बढ़ी है। इसके अतिरिक्त पिछले दस वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.53% थी जो साल 2000 से 2010 के बीच 0.57% की दर से नीचे रही।

प्रमुख बिन्दु

- 1970 के दशक में चीन ने एक बच्चे की नीति लागू की थी जिसके बाद से जनसंख्या वृद्धि की दर कम होती रही है। लेकिन 2011 से 2020 के दशक के आंकड़े बताते हैं कि अब यह ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है।
- पिछले दशक में चीन की जनसंख्या 5.38 प्रतिशत बढ़कर एक अरब 41 करोड़ हो गई है। 2010 में यह 5.84 फीसदी बढ़ी थी।
- 2016 में चीन ने 2020 तक आबादी को 1.42 अरब ले जाने का लक्ष्य तय किया था जिससे वह चूक गया है। 2016 में चीन ने एक बच्चे की नीति को बदलकर प्रति परिवार बच्चों की संख्या दो कर दी थी।
- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक चीन की आबादी बढ़ती रहेगी और अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद उसमें कमी होनी शुरू होगी। लेकिन अप्रैल में फाइनैंशल टाइम्स अखबार ने चीनी अधिकारियों के हवाले से खबर दी थी कि देश की जनसंख्या 2020 में पिछले साल के मुकाबले कम हुई है।
- चीन की ताजा जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी के 17.95 प्रतिशत 14 या उससे कम साल के हैं. 2010 में उनकी संख्या 16.6 प्रतिशत थी।

चीन में घटती जन्म दर

- 2016 से 2019 के बीच चीन की सालाना जन्मदर कमोबेश घटती ही रही है। हालांकि चीन ने 2020 की जन्मदर सार्वजनिक नहीं की है लेकिन 2016 को छोड़ दें तो हर साल इसमें कमी हुई है।
- चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार आने वाले समय में आबादी में अधिक उम्र वालों की संख्या बढ़ने से संतुलित विकास और जनसंख्या को लेकर दबाव बढ़ेगा। आबादी में 15-59 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की हिस्सेदारी 894 है जोकि 2010 की जनगणना के मुताबिक 6.79 घटी है।

जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट क्यों?

- जानकारों का मानना है कि चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर चिंताजनक स्तर पर पहुँच जाने के पीछे चीन की विवादास्पद 'वन चाइल्ड पॉलिसी' एक बड़ा कारण है। गौरतलब है कि चीन में जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने के लिए इस नीति को साल 1979 में लागू किया गया था।
- इस नीति के लागू होने के बाद जिन परिवारों ने नियमों का उल्लंघन किया, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा, उन्हें रोजगार का नुकसान हुआ और कभी-कभी गर्भपात के लिए भी मजबूर होना पड़ा। हालांकि साल 2016 में चीन की सरकार ने इस नीति को समाप्त कर दिया था और जोड़ों को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी थी।

3. मेक्सिको में मिली 'बातूनी' डायनासोर की नई नस्ल

चर्चा का कारण

- हाल ही में मेक्सिको के इतिहास और मानवशास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान ने एक नए डायनासोर की नई नस्ल खोजी है। जीवाश्म विज्ञानियों की एक टीम को उत्तरी मेक्सिको में 7.3 करोड़ साल पुराने अवशेष मिले। यह डायनासोर शाकाहारी था और संभवतः शांतिपूर्ण लेकिन बातूनी था।

प्रमुख बिन्दु

- जीवाश्म विज्ञानी (Palaeontologists) ने इसका नाम टीलैटोलोफस गैलोरम (Tilatolophus galorum) दिया है। इसके सिर पर रंगीन कलगी (Crested) लगी है।
- सबसे पहले 2013 में मेक्सिको के उत्तरी प्रांत कोवाउइला के जनरल सेपेडा इलाके में इसकी पूंछ मिली थी। फिर जैसे-जैसे खुदाई होती रही, वैज्ञानिकों को इसके सिर का 80 प्रतिशत हिस्सा, इसकी 1.32 मीटर की कलगी, जांघ की हड्डी और कंधे की हड्डी मिली।
- जीवाश्म वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह परभक्षियों को डरा कर भगाने के लिए या प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए तेज आवाजें निकालते थे।
- यह डायनासोर जिस हालत में मिला है उसके लिए करोड़ों साल पहले बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनी होंगी। उस समय चोहीला एक ट्रॉपिकल इलाका था।
- टीलैटोलोफस नाम स्थानीय नहुआतल भाषा के शब्द तलाहतोलि (मतलब शब्द या वाक्य) और यूनानी भाषा के शब्द लोफस (कलगी) से लिया गया है. इस डायनासोर की कलगी के आकार के बारे में संस्थान का कहना है कि यह मेसोअमेरिकी लोगों द्वारा उनकी प्राचीन हस्तलिपियों में बातचीत करने की क्रिया और ज्ञान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक चिह्न की तरह है।

अवशेष इतना सुरक्षित कैसे?

- मेक्सिको के इतिहास और मानवशास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार करीब 7.2 या 7.3 करोड़ साल पहले एक भीमकाय शाकाहारी डायनासोर संभवतः एक ऐसे जलाशय में मर गया होगा जो गाद से भरा हुआ होगा। उसका शरीर जल्द ही उसी गाद से ढक गया होगा और उसी में सदियों से संरक्षित रहा होगा।

इन डायनासोरों के सुनने की अद्‌भुत क्षमता

- इस नस्ल के डायनासोरों की सुनने की क्षमता ऐसी थी कि वो कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां भी सुन सकते थे। इसका मतलब है कि वो जरूर शांतिप्रिय लेकिन बातूनी रहे होंगे।
- जीवाश्म वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह 'परभक्षियों को डरा कर भगाने के लिए या प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए तेज आवाजें निकालते थे।'

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311

चर्चा का कारण

- हाल ही में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिव हिन्दुराव वाजे को मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मुंबई के पुलिस आयुक्त ने भारत के संविधान के प्रावधान 311 (2) (बी) के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है।

अनुच्छेद 311

- अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा।
- अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या रैंक में कम नहीं किया जाएगा जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।

क्या धारा 311 (2) के तहत बर्खास्तगी को सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जा सकती है?

- हां, इन प्रावधानों के तहत बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों में जा सकते हैं।
- **अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित व्यक्ति:**
  - संघ की सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं और किसी राज्य की सिविल सेवा, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति।
  - अनुच्छेद 311 के तहत दिये गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों, यानी लोक सेना अधिकारियों पर लागू होते हैं। वे रक्षाकर्मियों के लिये उपलब्ध नहीं हैं।

अनुच्छेद 311 (2) के तहत जांच की आवश्यकता कब नहीं होती?

- **अनुच्छेद 311 (2) (ए):** आरोप आपराधिक आरोपों के तहत है।
- **अनुच्छेद 311 (2) (बी):** यदि प्राधिकरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया है या उसे हटाने के लिए संतुष्ट है।
- **अनुच्छेद 311 (2) (सी):** यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं है।

2. लॉक डाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी

चर्चा का कारण

- हाल ही में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बाल विवाह की घटनाओं को देखकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह संबंधी मामलों में हो रही बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया है। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाल विवाह पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो चिंताजनक है।

प्रमुख बिन्दु

- कोविड 19 महामारी से पहले, भारत उन देशों में से एक था, जहां बाल विवाह के खिलाफ अभियान चरम पर था। भारत ने शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ कई प्रयास किए, किन्तु गरीबी और जागरूकता की कमी के चलते अभी भी बाल विवाह विभिन्न राज्यों किए जा रहे हैं।
- अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक चाइल्डलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल 2,180 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं।
- पिछले साल दिसंबर में 1,598 शिकायतों में से 365 इस श्रेणी से संबंधित थीं। अन्य शिकायतें अवैध रूप से गोद लेने, बाल तस्करी और बाल श्रम से लेकर जुड़ीं थीं।
- पहले जब हॉल, मंदिरों आदि में बाल विवाह होते थे तो कई ऐसे लोग थे जो संबंधित अधिकारियों या कार्यकर्ताओं को सचेत करते थे। जिस कारण विवाह नहीं हो पाता था किन्तु लॉकडाउन के कारण अब लोग घरों में बाल विवाह को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से चेतावनी तंत्र कमजोर हो गया है।
- सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट (Save the Children report) कहती है कि अगले पांच साल में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों की शादी जल्दी हो सकती है।
- गरीबी का सीधा संबंध बाल विवाह से है, बालिकाओं की पहुंच पहले से ही संसाधनों तक नहीं है। इसके अतिरिक्त उसे परिवार या समाज में बोझ माना जाता है। इन्ही सब वजहों से बालिकाएँ जल्दी शादी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

बाल विवाह का दुष्प्रभाव

- ऐसे समय में जब प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं, लड़की और उसके अजन्मे बच्चे का जीवन अधिक जोखिम में होता है।
- बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है जिससे उनपर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है।
- बाल विवाह, बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं।
- जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है, उसके स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसके कमाने और समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। उसे घरेलू हिंसा तथा एचआईवी / एड्स का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। खुद नाबालिग होते हुए भी उसकी बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण अक्सर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती हैं।
- बाल विवाह, समाज की जड़ों तक फैली बुराई, लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। यह आर्थिक और सामाजिक ताकतों की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम है।

भारत में बाल विवाह

- भारत में बाल विवाह में आई कमी की वजह से दुनियाभर में इस प्रथा के चलन में भी गिरावट आई है। यह कमी कई कारणों से हो सकती हैं जैसे अधिकमाताओं का साक्षर होना, लड़कियों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलना, सरकार के सख्त कानून और गांव के लोगों का शहरों की तरफ पलायन।
- लड़कियों की शिक्षा में तेजी से बढ़ोतरी, नाबालिग लड़कियों के लिए सरकार की योजनाएं और बाल विवाह का गैर कानूनी होने तथा इसके नुकसान पर सशक्त सार्वजनिक संदेश इस बदलाव के अन्य कारण हैं।

बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास

- स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण, पोषण एवं जल व साफ-सफाई पर मौजूदा योजनाओं को एक सिरे में बांधकर बाल विवाह की समस्या को सर्वांगीण रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।यह प्रयास एक बच्चे के संपूर्ण जीवनचक्र में बाल विवाह को रोकने के लिए है, खासतौर पर उन गूढ़ नकारात्मक सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देकर जो भारत में इस समस्या के पनपने के सबसे बड़े कारण हैं।
- भारत में 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। इसमें बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। जो माता-पिता अपने पुत्र पुत्रियों का बाल विवाह करवाते है तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपयों का दंड देने का प्रावधान है।

3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग

चर्चा का कारण

- हाल ही में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग की गई है।

मुख्य बिन्दु

- सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई है।
- याचिका में कहा गया है कि क्योंकि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिये प्रावधान नहीं हैं, इसलिए इनकी पारदर्शी नियुक्ति हेतु एक सक्षम प्रणाली होनी चाहिए। ताकि इस महत्वपूर्ण आयोग की स्वतन्त्रता प्रभावित ना हो और यह निष्पक्ष होकर कार्य कर सके।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करते हैं।

निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए पूर्व में की गई सिफारिशें

- वर्ष 1975 में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु तटस्थ कॉलेजियम की सिफारिश की गई थी। इसके बाद, वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की थी। वर्ष 2009 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम प्रणाली का सुझाव दिया था।

भारतीय निर्वाचन आयोग

- भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत के संविधान में उल्लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय

निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का निर्वहन और सफल संचालन सुनिश्चित करता है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। वर्तमान में, इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल बहुत कम 1 जनवरी 1990 तक ही रहा। इसके बाद इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। परन्तु बाद में फिर से 1 अक्टूबर 1993 को आयोग में दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और यह फिर से तीन सदस्यीय आयोग बन गया।

- आयोग के पास ऐसे उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, जो तय समय के भीतर और कानून के अनुसार निर्धारित तरीके से अपने चुनाव खर्चों का लेखा-जोखा आयोग के सामने पेश करने में विफल रहा है। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। अनुच्छेद 192 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में राज्यों के राज्यपाल निर्वाचन आयोग से परामर्श करते हैं।

निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल

- राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन करने की शक्ति है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना अन्य आयुक्तों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन

चर्चा का कारण

- किसानों की आय को बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र की भूमिका और व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) क्या है?

- फल, सब्जियाँ, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू आदि को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को साकार करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना को वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है।
- एमआईडीएच ने बागवानी फसलों की पैदावार करने वाले क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमश: 9% और 14% तक बढ़ा है।
- इसके अलावा, इस मिशन ने खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रणालियों को बढ़ावा दिया है, जिसने खेत की उत्पादकता और उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है।
- एमआईडीएच के लागू होने से न केवल बागवानी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि इसने भूख, अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल, गरीबी मुक्त, लैंगिक समानता जैसे सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है बाकी का 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। हालांकि भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है।

देश में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन

- बागवानी क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के कारण आज देश में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन कृषि उत्पादन से आगे निकल गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 25.66 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर बागवानी क्षेत्र का अब तक का सर्वाधिक 320.77 मिलियन टन उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में 27.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर बागवानी क्षेत्र का कुल उत्पादन 326.58 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की उप योजनाएँ

- **नारियल विकास बोर्ड:** नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 1981 में की गई थी। जिसका कार्य नारियल संबंधित खेती को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य बागवानी खेती को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं में दी जाने वाली अनुदान राशि में 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है।
- **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन:** यह सभी पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में काम करता है, जिसका उद्देश्य फल और औषधीय खेती को बढ़ावा देना है।
- **राष्ट्रीय बांस मिशन:** राष्ट्रीय बांस मिशन देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान रूप से कार्य करता है। जिसका उद्देश्य देश में बांस की खेती करने वाले किसानों को इसकी खेती के लिए उचित जानकारी देना और इसको बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना है।
- **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड:** भारत सरकार द्वारा साल 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गई थी। जिसका उद्देश्य बागवानी खेती से संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देकर व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने है।

चुनौतियाँ

- यह क्षेत्र फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और फसल कटाई के बाद के प्रबन्धन एवं सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे के बीच मौजूद अंतर की वजह से अभी भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

आगे की राह

- भारतीय बागवानी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, जो वर्ष 2050 तक देश के 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है।
- इस दिशा में किए जाने वाले अच्छे प्रयासों में सामग्री उत्पादन की रोपाई पर ध्यान केन्द्रित करना, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, एफपीओ के गठन और विकास जैसे कई प्रयास शामिल हैं।

2. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22

चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह किस्तों में जारी किए जाएंगे। इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिये की जाएगी।

सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना

- गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किश्तों में निवेश शुरू किया गया है।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता। यह फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जहां तक शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता।
- इस पर तीन साल के बाद लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा (मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा) वहीं इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बात रिडेंप्शन की करें तो पांच साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं।

कौन कर सकता है निवेश?

- बॉन्ड की बिक्री व्यक्तिगत रूप से यहां के निवासियों, हिंदू अविभाजित परिवार, न्यास, विश्वविद्यालय और परमार्थ संस्थानों को ही की जाएगी। इसमें व्यक्तिगत रूप से और हिंदू अविभाजित परिवार प्रति वित्त वर्ष न्यूनतम एक ग्राम सोने और अधिकतम चार किलो सोने के लिए निवेश कर सकते हैं।
- जबकि न्यास और इस प्रकार की अन्य इकाइयां प्रति वर्ष 20 किलो सोने में निवेश कर सकते हैं। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मनोनीत डाकघरों और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) के जरिये की जाएगी।

निवेश की सीमा

- स्कीम के तहत व्यक्तिगत निवेशक और हिंदू अविभाजित परिवार एक वित्त वर्ष में कम से कम एक ग्राम और अधिकतम चार किलोग्राम गोल्ड के लिए निवेश कर सकते हैं।
- ट्रस्ट और ऐसी ही दूसरी इकाइयां हर साल 20 किग्रा सोने में निवेश कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड की बिक्री बैंकों (Banks), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डाकघरों (Post Offices) और मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों (Stock Markets) के जरिये की जाएगी।

ब्याज दर

- निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से मुआवजा दिया जाएगा जो अंकित मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा।

भुगतान का विकल्प

- बॉन्ड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपये तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये की जा सकेगी।

3. ताउते चक्रवात

चर्चा का कारण

- हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते (Cyclone Tauktae) ने गुजरात सहित केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है।

ताउते का नामकरण

- इसका नाम म्यांमार ने दिया था। यह बर्मी शब्द है, जिसका मतलब है - अधिक शोर करने वाली छिपकली। चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत (डब्ल्यूएमओ/ईएससीएपी) पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन (पीटीसी) द्वारा किया जाता है।
- इस पैनल में 13 देश हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सउदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। ये देश तूफान के नामकरण का सुझाव देते हैं। पिछले साल हरेक देश ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की फेहरिस्त बनी थी।
- चक्रवातों का नाम सरल और छोटा रखा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि इनका अर्थ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील न हो या इनका भड़काऊ अर्थ न हो।

वर्गीकरण

- भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने इसे तीव्र तूफान बताया था, हालांकि अब मौसम विभाग ने कहा है कि 'ताउते' नाम का यह तूफान 'बेहद भीषण चक्रवाती तूफान' में बदल गया है।

अरब सागर से उत्पत्ति

- अरब सागर का चक्रवाती तूफानों का केंद्र बनते जाने के पीछे बीते 40 वर्षों में उसके तटीय इलाकों के तापमान (Sea Surface Temperatures या SST) में वृद्धि होना है। इन वर्षों में अरब सागर का तटीय तापमान 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है।
- अरब सागर का तटीय तापमान अक्सर बंगाल की खाड़ी के मुकाबले 1 से 2 डिग्री कम रहा करता था। चूंकि अब वहां का तापमान भी बढ़ रहा है, इसलिए तूफानों का उठना आम होता जा रहा है। यही कारण है कि केरल,गुजरात, महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों को भारी वर्षा और चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ रहा है।

चक्रवात का निर्माण कैसे होता है?

- जल बादल बनने से पहले वायुमंडल से गर्मी अवशोषित करता है और यह वाष्प में बदल जाता है। जब यह जल वाष्प वर्षा के रूप में वापस तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वायुमंडल में गर्मी का प्रसार होता है। यह गर्मी आसपास की हवा को गर्म कर देती है और फिर हवा ऊपर उठती है और जिसके कारण दबाव में गिरावट होती है। इसके परिणामस्वरूप, अधिक हवा तूफान के केंद्र की ओर आती है और चक्र निरंतर चलता रहत है।
- चक्रवात (साइक्लोन) घूमती हुई वायुराशि का नाम है। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के दो भेद हैं-
  1. उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone), तथा
  2. शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extra-tropical cyclone)
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तीव्र गोलाकार तूफान होता है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश है। ये तूफान दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घुमते हैं और उत्तरी गोलार्ध में एंटीक्लॉकवाइज घूमते हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाओं और भारी बारिश से चिह्नित किया जाता है। अत्यधिक स्थिति में, हवाएं 240 किमी प्रति घंटे से अधिक हो सकती हैं और प्रचंड रूप में वायु 320 किमी प्रति घंटे से अधिक हो सकती है।
- इन तेज हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश और विनाशकारी घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें तूफानी लहर भी कहा जाता है। मूल रूप से, यह समुद्र की सतह का एक उत्थान है जो सामान्य स्तर से 6 मीटर ऊपर पहुंच सकता है।
- दुनिया के उष्णकटिबंधीय (tropical) और उपोष्णकटिबंधीय (subtropical) क्षेत्रों में, उच्च हवाओं और पानी के संयोजन वाले ऐसे चक्रवात तटीय क्षेत्रों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

दुनिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न नाम

- अटलांटिक महासागर और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन (Hurricane) के रूप में जाना जाता है।
- पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून (Typhoon) के नाम से जाना जाता है।
- दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) के रूप में जाना जाता है।

4. बीमा बांस

चर्चा का कारण

- हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयंबटूर ने एक नवाचार करते हुए ऑक्सिजन पार्क का उदघाटन किया। यह पार्क करीब 1.45 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है।

बीमा बाँस (Beema Bamboo)

- इस पार्क में बांस के विशेष किस्म के पौधे लगाए जाएँगे। एक बीमा बांस विकसित होने पर 300 किलो ऑक्सिजन देता है।
- ये बीम बांस 80 टन कार्बनडाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। बीमा बांस बम्बुसा बालकोआ (Bambusa balcooa) से चयनित एक क्लोन है।
- यह एक उच्च बायोमास उपज देने वाली बांस की प्रजाति है। साथ ही, यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। यह दिन में डेढ़ फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है।
- इसके अलावा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बीमा बांस सबसे अच्छा कार्बन सिंक (carbon sink) है।

बीमा बांस का महत्व

- उन्हें हर फसल चक्र के बाद दोबारा उगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वे ऊतक संस्कृति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो इसे विभिन्न मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के ढलने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- बांस का कैलोरी मान कोयले के लगभग बराबर है। इस प्रकार, सीमेंट उद्योगों ने इस बांस को अपने बॉयलरों के लिए खरीदना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission)

- राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में लांच किया गया था।
- यह वर्तमान में 21 राज्यों में लागू किया जा रहा है।

5. तियानवेन-1

चर्चा का कारण

- चीन ने मंगल ग्रह के लिये जो मिशन भेजा था, उसका रोवर हाल ही में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर गया है।

मुख्य बिन्दु

- चीन ने 23 जुलाई, 2020 को 'तियानवेन-1' नामक मंगल ग्रह के लिये जो मिशन भेजा था। करीब सात महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद 'तियानवेन-1' मिशन ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है।
- 'तियानवेन-1' मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर का नाम 'झुरोंग' है।
- चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (सीएनएसए) ने हाल ही में बताया है कि 'झुरोंग' रोवर ने मंगल ग्रह पर यूटोपिया प्लैनिशिया नामक जगह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है।
- इसके साथ ही चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन के पहले यह कार्य अमेरिका कर चुका है। गौरतलब है कि अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी नासा ने कुछ ही समय पहले मंगल ग्रह पर परसीवरेंस नामक रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी।
- मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाले 'झुरोंग' रोवर का भार लगभग 240 किलोग्राम है तथा इसमें छह पहिए और चार सौर पैनल हैं।
- इससे पहले भारत ने भी मंगल ग्रह पर अपना मिशन (मंगलयान) भेजा था। हालांकि भारत ने अपने मंगल मिशन में रोवर को नहीं भेजा था।

अन्य मंगल मिशन

- 1971 में USSR मंगल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हालाँकि इसका 'मार्स 3' लैंडर विफल हो गया था। मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश अमेरिका है। 1976 के बाद से, इसने 8 सफल मार्स लैंडिंग की जिसमें नवीनतम वर्ष 2019 का 'इनसाइट' मार्स मिशन और वर्ष 2020 का मार्स रोवर परसिवरेंस (Mars Perseverance rover) है। मार्स रोवर परसिवरेंस ने हाल ही में मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है।

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सक्षम हो गई है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था, इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र है और उसने पहले प्रयास में ही ऐसा किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी 'होप मंगल मिशन' (Hope Mars Mission) को वर्ष 2020 में मंगल ग्रह के लिए लांच किया था।

6. स्किंक की नई प्रजाति

चर्चा का कारण

- हाल ही में पश्चिमी घाट (Western Ghats) से स्किंक (Skink) की नई प्रजाति मिली है।

स्किंक (Skink)

- पर्यावरणवादियों ने पश्चिमी घाट (Western Ghats) की नीलगिरि की पहाड़ियों से स्किंक (Skink) की नई प्रजाति का पता लगाया है। स्किंक (Skink) की इस नई प्रजाति को 'सबडॉलूसेप्स नीलगिरिएन्सिस' (Subdoluseps nilgiriensis) नाम दिया गया है। स्किंक की इस नई प्रजाति के नाम में 'नीलगिरिएन्सिस' शब्द नीलगिरि की पहाड़ियों के कारण दिया गया है। स्किंक की इस नई प्रजाति का शरीर लगभग 7 सेमी पतला है और यह रेतीले भूरे (sandy brown) रंग की है।

स्किंक (Skink)

- स्किंक (Skink), एक प्रकार के सरीसृप (reptile) जीव हैं। ये सरीसृपों के 'छिपकली वर्ग' के अंतर्गत आती हैं। स्किंक (Skink) के अंग बहुत कम विकसित होते हैं। इसलिए ये सर्प की तरह रेंगकर चलती हैं। यही कारण है कि मानव इन्हें जहरीली समझकर मार देते हैं। जबकि ये जहरीले नहीं होती हैं। स्किंक (Skink) का शरीर काफी चिकना होता है और यह बहुत फुर्तीली प्रजाति है। सामान्यतया स्किंक की प्रजातियाँ रेतीले मैदानों, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं।
- स्किंक की पूरी दुनिया में लगभग 1,602 प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से लगभग 62 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में स्किंक की प्रजातियाँ पश्चिमी घाट तथा भारतीय प्रायद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्किंक का भोजन दीमक, छोटी - छोटी मकड़ियां एवं अन्य कीट हैं। जंगल की आग, मानव द्वारा आवास निर्माण, ईट भट्ठा उद्योग एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के चलते स्किंक की प्रजातियाँ कम हो रही हैं।

पश्चिमी घाट (Western Ghats)

- पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों (यथा- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात) में ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है।
- पश्चिमी घाट में दक्षिण-पश्चिम मानसून से भारी वर्षा होती है। इसलिए यह भारत के वर्षण प्रचुर क्षेत्रों में से एक है और यहाँ काफी अधिक जैव विविधता पायी जाती है।
- भारत के प्रायद्वीप की जलवायु को पश्चिमी घाट महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।
- प्रायद्वीपीय भारत का लगभग संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट ही है।
- पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं। इसलिए ये मानसूनी हवाओं में अवरोध उत्पन्न कर वर्षा कराते हैं।
- पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति (Gadgil and Kasturirangan Committee) का गठन किया गया था। जिसने इसे तीन पर्यावरण संवेदनशील जोन (Ecologically Sensitive Zones- ESZ) में बांटने का सुझाव दिया था।
- इसके अतिरिक्त समिति का अन्य प्रमुख सुझाव था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थिकी प्राधिकरण (Western Ghats Ecology Authority- WGEA) का गठन किया जाये।
- भारत में पश्चिमी घाट, जैव विविधता का एक समृद्ध हॉटस्पॉट है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों अवस्थित हैं।

नीलगिरी के बारे में

- नीलगिरि तमिलनाडु में स्थित पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, जिसका कुछ हिस्सा केरल और कर्नाटक में भी आता है।
- इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोड्डाबेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है।
- सितंबर 1986 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फियर प्रोग्राम के तहत इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था।
- वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जीवमंडल भंडार है।
- इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रमुख स्थानीय आदिवासी समूह हैं: बडगा, टोडा, कोटा, इरुल्ला, कुरुम्बा, पनिया, आदियान, अल्लार, मलायन आदि।
- इस पर्वत माला के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है-
  - मुकुरथी
  - बांदीपुर
  - नागरहोल
  - शांत घाटी
  - एरालम वन्यजीव अभयारण्य
  - मुदुमलाई

7. जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रासफॉर्मेशन (Digital Transformation of Tribal Schools) के लिए संयुक्त पहल को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

मुख्य बिन्दु

- भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी, कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential Schools- EMRS) और आश्रम स्कूल (Ashram Schools) जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम 'सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण' के तहत स्कूल और अन्य संस्थानों के लिए डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी ऑनलाइन कार्यक्रम 'सफलता के लिए युवाओं का सशक्तिकरण' के तहत माइक्रोसॉफ्ट के साथ यह समझौता किया गया है।
- इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है।
- इसके अलावा, इस प्रयास द्वारा भारत में जनजातीय छात्रों को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आवश्यक कौशल मुहैया कराया जाएगा। यह एआई और कोडिंग के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होने के साथ एक नया अध्याय भी शुरू करेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 250 ईएमआरएस स्कूलों को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें से 50 ईएमआरएस स्कूलों को गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पहले चरण में 500 प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School-EMRS) योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में की गई थी।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना के तहत प्रथम स्कूल, वर्ष 2000 में महाराष्ट्र में खोला गया था।
- उल्लेखनीय है कि शिक्षा किसी भी देश और समुदाय के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है। शिक्षा से ही सामाजिक और आर्थिक विकास संभव है। आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें शिक्षित करना नीति निर्माताओं के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है।
- ऐसी परिस्थितियों में लक्षित समूह तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना वरदान साबित हो रही है।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी नए आयाम खोले हैं।

आश्रम स्कूल के बारे में

- आदिवासी क्षेत्रों (विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों) में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार वर्ष 2008-09 से आश्रम स्कूल (Ashram Schools) को बढ़ावा दे रही है। आश्रम स्कूलों में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए शिक्षा के अनुकूल वातावरण में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

8. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) से संबन्धित आंकड़े जारी किए हैं।

मुख्य बिन्दु

- उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अप्रैल, 2021 (अनंतिम) और फरवरी, 2021 (अंतिम) के लिए थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) से संबन्धित आंकड़े जारी किए हैं। गौरतलब है कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत

सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

- इन आंकड़ों में सरकार ने बताया है कि अप्रैल, 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49 प्रतिशत (अनंतिम) रही है।
- अप्रैल 2021 के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अधिक रही है जो मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम, खनिज तेलों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बढोतरी के कारण हुई।

मुद्रास्फीति (Inflation) क्या है?

- मुद्रास्फीति का अभिप्राय, दैनिक जीवन में लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं (यथा- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन और परिवहन इत्यादि) की कीमतों में होने वाली वृद्धि से होता है। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों द्वारा मापा जाता है - थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI)।

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)

- थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल थोक मूल्य सूचकांक भारत में व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज्यादा भार दिया जाता है। इसे भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी किया जाता है।
- थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। उल्लेखनीय है कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनंतिम आंकड़े देश भर में संस्थागत स्रोतों और चुनी हुई विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं और हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस) को जारी किए जाते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index)?

- खुदरा स्तर पर महँगाई मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जुड़ाव सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से होता है। वर्तमान में भारत में पांच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) हैं, जिनमें से प्रमुख चार निम्नलिखित हैं-

1. औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिये सीपीआई अर्थात औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [Consumer Price Index: Industrial Workers (CPI:IW)]
2. कृषि मजदूर (Agricultural Labourer-AL) के लिये सीपीआई
3. ग्रामीण मजदूर (Rural Labourer-RL) के लिये सीपीआई
4. सीपीआई (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)

- उपर्युक्त में से प्रथम तीन को श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय 'श्रम ब्यूरो' द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। जबकि चौथे प्रकार की सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986-87 है।

9. रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ

चर्चा का कारण

- एक शोध के मुताबिक रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ (Red-Eared Slider Turtle) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल निकायों की जैव विविधता के लिये एक बड़ा खतरा बन सकता है।

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ के बारे में

- इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेकेमीस स्क्रिप्टा एलिगेंस (Trachemys Sscripta Elegans) है। पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला यह कछुआ मूल रूप से अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में पाया जाता है।
- रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ अपने छोटे आकार और रंग के कारण पालतू प्रेमियों, विशेष रूप से बच्चों में बेहद लोकप्रिय है।
- इस कछुए के कानों के समीप लाल धारियां पायी जाती हैं तथा यह किसी भी सतह से पानी में जल्दी से सरक जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ पड़ा है।

रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ एक आक्रामक कछुआ

- रेड-इयर्ड स्लाइडर्स लचीले जीव होते हैं और कई प्रकार की स्थितियों (जैसे विभिन्न पानी के तापमान, पीएच और कठोरता) को सहन करते हैं।
- जंगल में रहने वाले, लाल कान वाले स्लाइडर कछुए जलीय वनस्पतियों, छोटी मछलियों मेंढक और मृत मछली को खाते हैं। चूँकि यह एक आक्रामक प्रजाति है और तेजी से वृद्धि करती है। साथ ही यह कछुआ मूल प्रजातियों के भोजन को भी खा जाती है, जिससे स्थानीय प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
- छोटे कछुए को माचिस की डिब्बी में भी रखा जा सकता है, लेकिन यह तेजी से बढ़ता है। वयस्क कछुओं को बहुत सारे जलीय पौधों की आवश्यकता होती है। साथ ही वे सर्वाहारी भी हैं। एक बार जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें रखना मुश्किल हो जाता है, लोग कभी-कभी उन्हें जल निकायों में छोड़ देते हैं, जिससे पारितंत्रीय प्रतिकूलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

राफेल नडाल

एंड्रिया मेजा

डॉ. शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड

नुक्लू फोम

सुखदेव थापर

तलवारबाज भवानी देवी

नीरा टंडन

राफेल नडाल

- हाल ही में स्पेन के राफेल नडाल ने इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने विश्व के नंबर-1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ये जीत दर्ज की. राफेल नडाल ने दो घंटे 49 मिनट तक चले इस मुकाबले में जोकोविच को 7-5, 1-6, 6-3 से हराकर इटैलियन ओपन के खिताब पर कब्जा किया।

10वीं बार यह खिताब जीता

- राफेल नडाल 12वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने 10वीं बार यह खिताब जीता. वहीं नडाल और जोकोविच के बीच छठी बार इटैलियन ओपन का खिताबी मुकाबला खेला गया जिसमें स्पेनिश खिलाड़ी ने सर्बियाई खिलाड़ी को पराजित किया।
- राफेल नडाल ने इसके साथ ही जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने की बराबरी कर ली। यह चौथा मौका है जब

उन्होंने एक टूर्नामेंट दस या उससे अधिक बार जीता। उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है।

एंड्रिया मेजा

- हाल ही में मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स, 2020 का खिताब जीता है। विदित हो कि मिस यूनिवर्स के 69वें संस्करण का आयोजन 16 मई, 2021 को फ्लोरिडा, अमेरिका में किया गया। इसे 2020 में COVID-19 महामारी के कारण रद्द किया गया था। एंड्रिया मेजा ने दुनिया भर की 74 प्रतियोगियों को हराया। ब्राजील की जूलिया गामा (Julia Gama) उपविजेता रहीं और पेरू की जानिक मैकेटा (Janick Maceta) तीसरे स्थान पर रहीं।

मिस इंडिया

- मिस इंडिया एडलाइन कैस्टेलिनो (Adline Castelino) ने शीर्ष चार में जगह बनाई।

एंड्रिया मेजा कौन है?

- 26 साल की एंड्रिया मेजा का जन्म 13 अगस्त को चिहुआहुआ शहर में हुआ था और वे अल्मा कार्मोना और सैंटियागो मेजा की बेटी हैं। उनकी दो छोटी बहनें हैं। उन्होंने साल 2017 में चिहुआहुआ की ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ली। एंड्रिया ने अपनी जीत के साथ एक इतिहास भी रच दिया, क्योंकि वे

मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बनीं। एंड्रिया मेजा एक मॉडल होने के साथ-साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, जो लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा के बारे में काफी मुखर हैं।

डॉ. शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड

- हाल ही में भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ, डॉ. शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड (Dr Shakuntala Hark Singh Thilstad) को वर्ष 2021 का "विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Award)" मिला है। उन्होंने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। हर साल, समिति एक ऐसे व्यक्ति का चयन करती है, जिसे उपाधि और 250,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है।
- विश्व खाद्य पुरस्कार ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि बांग्लादेश की छोटी मछली प्रजातियों पर डॉ. शकुंतला द्वारा किए गए शोध, सभी स्तरों पर समुद्री खाद्य प्रणाली के लिए पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में मददगार साबित होंगे। इसकी मदद से एशिया और अफ्रीका में रहने

वाले लाखों गरीबों को बहुत पौष्टिक आहार मिलेगा।

नुक्लू फोम (Nuklu Phom)

- हाल ही में नागालैंड के नुक्लू फोम (Nuklu Phom) ने 2021 का व्हिटली अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार पाने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं। उल्लेखनीय है कि इसे "ग्रीन ऑस्कर" (Green Oscar) के नाम से भी जाना जाता है।

व्हिटली अवाड्र्स

- व्हिटली अवाड्र्स को Whitley Fund for Nature द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे जमीनी स्तर के नेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें संदर्भ, आवेदन और साक्षात्कार की प्रक्रिया शामिल है। व्हिटली फंड फॉर नेचर 1994 में एडवर्ड व्हिटली (Edward Whitley) द्वारा स्थापित किया गया था। इसने अब तक दो मिलियन पर्यावरणीय नायकों के काम का समर्थन करने के लिए 16 मिलियन पाउंड दिए हैं।

नुक्लू फोम

- नुक्लू फोम "जैव विविधता शांति गलियारे" (Biodiversity Peace Corridors) बना रहे हैं। वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अलावा वह स्वास्थ्य, शिक्षा और सूक्ष्म वित्त के लिए अपने कार्यों का विस्तार करते हैं। लेमासाचेनलोक सोसायटी (Lemasachenlok Society) की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी ने अमूर फाल्कन्स (Amur Falcons) के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम किया है। नुक्लू फोम को "नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन" (Amur Falcon Man of Nagaland) के रूप में जाना जाता है।

अमूर फाल्कन

- अमूर फाल्कन उत्तरी चीन और साइबेरिया में प्रजनन करते हैं। सर्दियों के दौरान, अमूर फाल्कन भारत में और फिर अरब सागर से दक्षिणी अफ्रीका की ओर पलायन करते हैं। बढ़ती चिंता यह है कि लोगों ने अमूर फाल्कन का शिकार करना शुरू कर दिया है। भारत में, सालाना 14,000 से अधिक अमूर बाज का शिकार किया जाता है। राज्य सरकारों ने अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बावजूद भी अमूर बाज का शिकार बढ़ता ही जा रहा है। इसे IUCN द्वारा "कम चिंताजंक" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नागालैंड को "Falcon Capital of the World" कहा जाता है।

सुखदेव थापर (Sukhdev Thapar)

- सुखदेव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रान्तिकारी थे। उनका पूरा नाम सुखदेव थापर था। सुखदेव महान क्रान्तिकारी भगत सिंह के बचपन के मित्र थे। जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत को अंग्रेजों की बेंड़ियों से मुक्त कराने के लिये समर्पित कर दिया और एक साथ भारत माँ के लिये शहीद हो गये।
- सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल थापर और इनकी माता का नाम रल्ली देवी था। इनके जन्म से तीन माह पूर्व ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और इनका लालन-पालन इनकी माता ने किया था।
- सुखदेव थापर की मृत्यु 23 मार्च 1931 (आयु 23 वर्ष) को लाहौर , पंजाब , ब्रिटिश भारत में (अब पंजाब, पाकिस्तान में) नई दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम विस्फोटों में इन्हें दोषी ठहराया गया जिसके बाद, सुखदेव और इन्हें साथियों को गिरफ्तार किया गया, और इन्हें फासी पर लटका दिया गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गयी।

सुखदेव थापर का करियर

- सुखदेव जब पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी मित्रता लाहौर कॉलेज में ही भगत सिंह, यशपाल और जयदेव गुप्ता से हुई। सुखदेव की उम्र जब करीब 12 साल की थी तब 1919 में हुए जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ। सुखदेव के मन पर भी इस घटना का बड़ा असर हुआ था और आगे चलकर सुखदेव ने साल 1926 में भगत सिंह, यशपाल और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों के साथ 'नौजवान भारत सभा' का गठन किया था। सभी क्रान्तिकारियों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 8-9 सितम्बर 1928 को फिरोजशाह कोटला के मैदान में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक की स्थापना की थी। जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखे जाने का सुझाव दिया और इस संगठन के पंजाब प्रान्त के नेता के रुप में चुने गए। सुखदेव ने बहुत से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया है जैसे 1929 का "जेल भरो आंदोलन"। लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला करने वाले जे. पी. साण्डर्स को गोली मारते समय भगत सिंह को एक दो पुलिसकर्मियों ने देख लिया था।

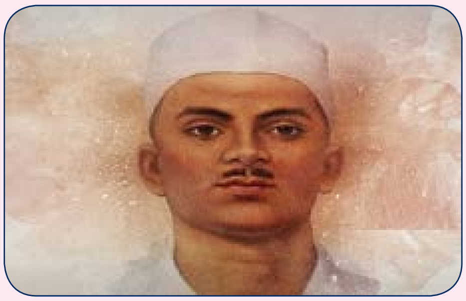

- 20 दिसम्बर 1928 को सुखदेव ने भगत सिंह के भेष को बदलकर उन्हें लाहौर से फरार करने में मदद की थी। सुखदेव को 07 अक्टूबर 1930 को विशेष न्यायिक सत्र द्वारा साण्डर्स की हत्या की साजिश करने के जुर्म में भगत सिंह और राजगुरु के साथ फाँसी की सजा की घोषणा हुई थी।

तलवारबाज भवानी देवी

- तलवारबाज (Sabre Fencer) भवानी देवी, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। इस वर्ष मार्च में बुडापेस्ट विश्व कप के बाद समायोजित आधिकारिक रैंकिंग (Adjusted Official Ranking- AOR) पद्धति के माध्यम से कोटा हासिल किया है। उन्होंने बांस के डंडे से प्रशिक्षण लेकर अपने करियर की शुरुआत की थी। भवानी देवी के दिवंगत पिता एक पुजारी थे और माँ एक गृहिणी हैं। 2017 में आइसलैंड में पहली इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाली भवानी वो महिला हैं जिन्होंने पहली बार तलवारबाजी में पदक जीतकर उसे भारत की झोली में डाला था. 2004 में तलवारबाजी को करियर चुनने वाली भवानी 8 बार की नेशनल चौंपियन हैं

नीरा टंडन

- भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन वर्तमान में अमेरिका के प्रगतिशील थिंक-टैंक, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस (CAP) की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत हैं। नीरा टंडन इससे पूर्व अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में स्वास्थ्य सुधारों हेतु वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।

सप्ताह के चर्चित स्थान

ईरान का फरजाद-बी गैस फील्ड

‘विंचकंब’ शहर

नाइजीरिया की नोख संस्कृति

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

सुलावेसी द्वीप

कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन

अंटार्कटिका

ईरान का फरजाद-बी गैस फील्ड

- हाल ही में ईरान ने फरजाद-बी गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। ज्ञातव्य है कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है।
- सरकारी स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) ने 2008 में फारसी अपतटीय अन्वेषण ब्लॉक में एक विशाल गैस क्षेत्र की खोज की थी। OVL और उसके सहयोगियों ने खोज के विकास के लिए 11 अरब अमेरिकी डॉलर तक के निवेश की पेशकश की थी, जिसे बाद में फरजाद-B नाम दिया गया।

यह समझौता कब हुआ?

- नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी और पेट्रोपार्स ग्रुप के बीच यह समझौता तेहरान में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री की मौजूदगी में 17 मई 2021 को हुआ। बता दें कि फरजाद-बी गैस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है। इसमें से 60 प्रतिशत तक गैस निकाली जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस गैस फील्ड में गैस कडेंनसेट्स हैं, जिसमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है।

फरजाद-बी गैस फील्ड की खोज

- रिपोर्ट के अनुसार, इस गैस फील्ड से अगले पांच साल तक हर रोज 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। फरजाद-बी गैस फील्ड की खोज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने पर्शियन गल्फ यानी फारसी ऑफसोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में साल 2008 में की थी।

'विंचकंब' शहर

- विंचकंब एक उल्कापिंड (Meteorite) है। जिसे ब्रिटेन में राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2021 में ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर के 'विंचकंब' (Winchcombe) नामक शहर में, 'विंचकंब उल्कापिंड' का एक हिस्सा पृथ्वी की सतह पर गिरा था।

क्या होते हैं उल्का (Meteoroid), उल्कापात (Meteor) तथा उल्कापिंड (Meteorite)?

- उल्का, आकार में धूमकेतु अथवा क्षुद्रग्रह से भिन्न होते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते है।
- उल्कापात, जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाती है। उस समय होने वाली इस प्रकाशीय घटना को उल्कापात कहा जाता है, जिसे 'टूटता तारा' भी कहते है।
- उल्कापिंड, उसे कहते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट होने से बच जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर आकर टकराती है।

नाइजीरिया की नोख संस्कृति

- हाल ही में शोधकर्ताओं ने मध्य नाइजीरिया से नोख संस्कृति के 3500 साल पुराने बर्तन में मधुमक्खियों के अवशेषों की पहचान की है जो अफ्रीका महाद्वीप में शहद संग्रह का सबसे पुराना प्रत्यक्ष प्रमाण है।

नोख संस्कृति के बारे में

- अफ्रीका में सबसे पुरानी आलंकारिक कला का प्रतिनिधि करने वाली मध्य नाइजीरिया के नोख संस्कृति का कालक्रम 1,500 ईसा पूर्व और कॉमन एरा की शुरुआत के बीच है। इस संस्कृति को विशेष रूप से टेराकोटा मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नोख संस्कृति के प्राचीन टेराकोटा पश्चिम अफ्रीका के जीवन और समाज की जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। विदित हो कि 1943 में नाइजीरिया में जोस पठार के दक्षिणी और पश्चिमी ढलानों पर टिन के खनन कार्यों के दौरान नोख संस्कृति का खोज किया गया था।

नाईजीरिया के बारे में

- यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएँ पश्चिम में बेनीन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से

लगती हैं। इस देश के बड़े शहरों में अबुजा, इबादान, कानो, जोस और बेनिन शामिल हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इस देश की आबादी सबसे अधिक है।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो

- हाल ही में दो मुस्लिम गुटों के बीच संघर्ष के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (Democratic Republic of Congo) ने 30 लोगों को मौत की सजा सुनाई है।

संघर्ष का कारण

- ईद समारोह आयोजित करने के अधिकार को लेकर कांगो के किंशासा (Kinshasa) शहर में मार्टर्स स्टेडियम के सामने दो मुस्लिम समूह आपस में भिड़ गए थे। इस संघर्ष के दौरान एक पुलिस कर्मी की मृतु हो गई थी और अनेक लोग घायल हो गए थे। ईद के दौरान बड़े पैमाने पर किंशासा में जश्न मनाया जाता है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में

- यह देश अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जिसका कुछ भू-भाग अंध महासागर से मिलता है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान, पूर्व में यूगांडा, रवांडा और अंगोला, पश्चिम में कांगो गणराज्य लगी हुई हैं। पूर्व में तंगानयिका झील

इस देश को तंजानिया से अलग करती है। कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 11वाँ सबसे बड़ा देश है। इस देश में लगभग 10% मुस्लिम आबादी है।

सुलावेसी द्वीप

- हाल ही में पुरातत्त्वविदों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है इस गुफा कला में जंगली सुअर को चित्रित किया गया है।

सुलावेसी गुफा कलाकृति के बारे में

- सुलावेसी जंगली सुअर चित्रकला कम-से-कम 45,500 वर्ष पुरानी है। यह चित्रकारी लाल गेरूए रंग से की गई है। पुरातत्त्वविद एडम ब्रूम के अनुसार सुलावेसी की लेंग टेडोंगगने गुफा में मिली पेंटिंग दुनिया में गुफा कलाकृति का सबसे पुराना नमूना है। यह गुफा एक घाटी में है जो कि बाहर से चूना-पत्थर की चट्टानों के कारण बंद हो गया था। इस गुफा में जंगली सुअर को छोटी सी शिखा और आँखों के सामने सींग सदृस्य आकृति के साथ दर्शाया गया है। कई हजार वर्षों से सुलावेसी में सुअरों का शिकार मनुष्यों द्वारा किया जा रहा था। इस शैल कलाओं में सबसे अधिक संख्या में चित्रित जानवर है, इससे

यह प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग इनका उपयोग भोजन के रूप किया करते थे।

कोलंबो पोर्ट सिटी

- हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने संसद में 'कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन' नाम का एक बिल पेश किया है। इस बिल में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में समुद्र किनारे 1 अरब 40 करोड़ रुपये की लागत से एक पोर्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। इस बिल का पूरे श्रीलंका में भारी विरोध किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह एक कर-मुक्त विदेशी अंत:क्षेत्र (Enclave) है, इसका वित्त पोषण चीन द्वारा किया जायेगा। इसे श्रीलंका द्वारा सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर पेश किया गया है।
- यह श्रीलंका में चीन द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा एकल विदेशी निवेश है।
- पोर्ट सिटी के भीतर कर्मचारी द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन कर-मुक्त होंगे और इन क्षेत्रों में लेनदेन में विदेशी मुद्रा की प्रधानता रहेगी।
- इस बिल के तहत पोर्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और ऑथराइजेशन के संबंध में एक कमीशन गठित करने की बात कही गई है। इस कमीशन में प्रांतीय अधिकारियों के अलावा विदेशियों की एक टीम भी होगी जो राष्ट्रपति के अलावा किसी और के प्रति जवाबदेह नहीं होगी।

- निवेश-अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस आयोग को विशेष शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
- सिविल सोसायटी समूह और श्रमिक संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना देश की संप्रभुता, संविधान और श्रम अधिकारों का उल्लंघन करती है।

अंटार्कटिका

- हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूट कर अलग हुआ है। इसकी चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर और इसकी लंबाई करीब 170 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,320 वर्ग किलोमीटर का है। इस हिमखंड को वैज्ञानिकों ने 'ए-76' नाम दिया है।

अंटार्कटिका के हिमखंड के बारे में

- यह हिमखंड अंटार्कटिका में मौजूद ग्लेशियर रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर वेडेल सागर में गिर गया है।
- यह हिमखंड आकर में स्पेनिश द्वीप मजोर्का से भी बड़ा है और प्यूर्टो रिको से करीब आधा है।
- यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई हिमखंड ग्लेशियरों से टूटकर अलग हुआ है। इससे पहले ए-23ए हिमखंड दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड था, जिसका आकार करीब 3,880 वर्ग किमी है। इस साल की शुरुआत में फरवरी में ब्रंट आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ हिमखंड ए-74 आकार में केवल 1,270 वर्ग किलोमीटर बड़ा था।

हिमखंड टूटने का कारण

- इन हिमखंडों को टूटने के लिए बहुत से वैज्ञानिक प्राकृतिक चक्र को जिम्मेवार मानते हैं। पर यह भी सच है कि जिस तेजी से तापमान में वृद्धि हो रही है उसके चलते ग्लेशियरों के पिघलने की दर काफी बढ़ गई है। जिसका असर इन ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) के अनुसार 2020 इतिहास का सबसे गर्म वर्ष था, जिसका प्रभाव इन ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है और यह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं।
- दुनिया भर में जमी बर्फ के पिघलने की रफ्तार, तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। इसके पिघलने की रफ्तार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। 1990 में यह 80,000 करोड़ टन प्रति वर्ष की दर से पिघल रही थी वो 2017 में बढ़कर 130,000 करोड़ टन प्रति वर्ष हो गई है। जिसका

मतलब है कि यह 1990 की तुलना में 65 फीसदी ज्यादा तेजी से पिघल रही है।

प्रभाव

- इस हिमखंड के टूटने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी और यह हिमखंड ग्लेशियर्स के बहाव और बर्फ की धाराओं की गति को धीमा कर सकता है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटारर्कटिका धरती के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेजी से गरम हो रहा है। अंटारकर्टिका में बर्फ के रूप में इतना पानी जमा है जिसके पिघलने पर दुनियाभर में समुद्र का जलस्तर 200 फुट तक बढ़ सकता है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

विश्व कृषि-पर्यटन दिवस

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह

विश्व कृषि-पर्यटन दिवस

- हाल ही में विश्व कृषि-पर्यटन दिवस (World Agri-Tourism Day) मनाया गया। यह हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 2021 में, इस दिवस का विषय: 'कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत् उद्यमिता के अवसर' (Rural Women Sustainable Entrepreneurship Opportunities through Agri Tourism) है। 16 मई, 2021 को देश भर में 14वें विश्व कृषि-पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

क्या है कृषि पर्यटन?

- कृषि पर्यटन का आशय पर्यटन के उस रूप से है, जिसमें ग्रामीण संस्कृति को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन के समान ही होता है, यद्यपि इसमें प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया जाता है। कृषि-पर्यटन में शहरी पर्यटक किसानों के घर में रहते हैं। अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं। इसके अलावा, वे लोक गीतों और नृत्यों का आनंद लेते हैं। वे ताजा कृषि उपज खरीदते हैं। बदले में, किसान पर्यटकों को आवास प्रदान करते हैं और उनके प्रवास के दौरान उनका मनोरंजन करते हैं।
- उद्देश्य विश्व कृषि-पर्यटन दिवस का लक्ष्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। विशेषज्ञों की मानें तो कृषि पर्यटन में कृषि आय बढ़ाने और एक गतिशील, विविध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। कई विकसित देशों में कृषि पर्यटन, पर्यटन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसे कृषि तथा संबद्ध व्यवसाय के मूल्यवर्द्धन के रूप में देखा जा सकता है, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बहु-क्रियाशील प्रकृति के इष्टतम लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। महाराष्ट्र, देश में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र में वर्ष 2005 में कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) का गठन किया गया था।

- **सर्वेक्षण:** कृषि पर्यटन विकास निगम के सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 0.56 मिलियन पर्यटकों ने कृषि-पर्यटन केंद्रों का दौरा किया। यह 2019 में बढ़कर 0.61 मिलियन और 2020 में 0.78 मिलियन हो गया है।
- **पृष्ठभूमि:** महाराष्ट्र देश में कृषि-पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। सितंबर 2020 में, महाराष्ट्र ने कृषि-पर्यटन नीति (Agro-Tourism policy) पारित की। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

- अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या विश्व परिवार दिवस न केवल एक स्वस्थ और अच्छी तरह से संतुलित परिवार के महत्व को बढ़ावा देता है, बल्कि आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के ज्ञान को भी बढ़ाता है जो परिवारों को प्रभावित करते हैं। यह दिन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन (Universal Peace Federation) द्वारा भी मनाया जाता है क्योंकि वे परिवार को एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा मानते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020: थीम

- अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2020 का थीम है "Families in Development: Copenhagen - Beijing $ 25"।
- कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (Copenhagen Declaration and Beijing Platform for Action) की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है जो सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक संकटों में के समय पर आई है। COVID-19 महामारी सबसे कमजोर व्यक्तियों और परिवारों की रक्षा करने वाली सामाजिक नीतियों में निवेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। वो परिवार ही हैं जो संकट का खामियाजा भुगतते हैं, अपने सदस्यों को नुकसान से बचाते हैं, और साथ ही साथ अपने काम की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं।
- सम्पूर्ण विश्व COVID-19 के संकट से संघर्ष कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को सभी के लिए अधिक समानता को बढ़ावा देने के तरीके पर पुनर्विचार करने और बदलने का एक वास्तविक अवसर मिला है। ऐसा करने पर, परिवारों में अधिक समानता के बिना लिंग

समानता प्राप्त नहीं होगी, और इस पर, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एक दूरदर्शी रोडमैप प्रदान करता है और बताता है कि हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस: इतिहास

- 9 दिसंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (United Nation General Assembly)

ने प्रस्ताव 44/82 में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की घोषणा की। 1993 में, जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव संख्या (A/RES/47/237) के द्वारा हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करना है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है?

- अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व और इसके मूल्य को समझाना है. साथ ही, उन मुद्दों को उजागर करना आवश्यक है जो दुनिया भर में परिवारों को प्रभावित करते हैं। यह दिन यह भी दर्शाता है कि वैश्विक समुदाय समाज की प्राथमिक इकाइयों के रूप में परिवारों के महत्व को बताती है और दुनिया भर में स्थिति के अनुसार अपनी चिंता को उजागर करती है। इस दिन परिवारों की परिस्थितियों से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी प्रकाश डाला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस दिन ने दुनिका में कई देशों को प्रेरित किया है कि वे भी परिवार दिवस मनाएं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें जो कि समुदाय पर आधारित हो और परिवार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे।

शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Living Together in Peace) 2018 से हर साल 16 मई को मनाया जाता है। यह दिन जाति, लिंग, धर्म और भाषा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने, मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाने के लिए शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of Living Together in Peace) स्थापित किया गया था। 1997 में, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 को शांति की संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष (International Year for Culture of Peace) के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पारित किया था। 1999 में, संयुक्त राष्ट्र ने "Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace" नामक एक प्रस्ताव अपनाया।यह शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक जनादेश के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर, 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता समावेशन, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को नियमित रूप से संगठित करने हेतु प्रतिवर्ष 16 मई को इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस दिवस का

उद्देश्य मतभेद और विविधता में एकजुटता और सद्भाव के साथ रहना और कार्य करना। साथ ही शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया का निर्माण करने के लिए, मतभेदों और विविधता में एकजुट होकर, एक साथ रहने और कार्य करने की इच्छा को बनाए रखना है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस

- प्रत्येक वर्ष, 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस (International Day of Light) मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका का जश्न मनाता है। इस वर्ष की थीम: 'Trust Science' है।

पृष्ठभूमि

- यह दिन वर्ष 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन को चिह्नित करने के लिये मनाया जाता है। क्योंकि LASER का पहला सफल ऑपरेशन 16 मई 1960 को एक अमेरिकी इंजीनियर एवं भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन द्वारा किया गया था। प्रकाश विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों की उपलब्धियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम वर्ष 2015 में 'प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय' वर्ष मनाया था, इसके पश्चात् वर्ष 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आयोजित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का महत्व

- प्रतिवर्ष 16 मई को विश्व भर में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता

है। प्रकाश हमारे जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश ही जीवन के मूल में है। प्रकाश के अध्ययन ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, नैदानिक प्रौद्योगिकी और उपचार में जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धति एवं लाइट-स्पीड इंटरनेट और इसी प्रकार की अन्य खोजों से समाज में क्रांति ला दी है तथा ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ को महत्त्वपूर्ण आकार दिया है

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का उद्देश्य आम जनमानस के दैनिक जीवन में प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति एवं सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु 'प्रकाश' की क्षमता के दोहन का आह्वान करता है। इस दिवस को यूनेस्को के 'इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम' (IBSP) से प्रशासित किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के लक्ष्य

- दैनिक जीवन में प्रकाश-आधारित प्रौद्योगिकियों के महत्व में सार्वजनिक समझ में सुधार करना
- युवा लोगों के लिए विज्ञान को लक्षित करने वाली गतिविधियों का निर्माण करना
- प्रकाश, कला और संस्कृति के बीच की कड़ी को उजागर करने के लिए
- प्रकाश प्रौद्योगिकियों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए

प्रकाश प्रौद्योगिकियां

- रेडियो तरंगें और गामा किरणें ब्रह्मांड की उत्पत्ति में अंतर्दृष्टि (insights) प्रदान करती हैं।
- इसके अलावा, नैनो फोटोनिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स जैसे शोध नई मौलिक खोजों को प्रेरित करते हैं।
- फोटोनिक्स समर्थित उद्योग अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
- स्मार्टफोन की शक्ति को बेहतर दृष्टि प्रदान करने में फोटोनिक्स एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

- प्रतिवर्ष 17 मई को पूरे विश्वभर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है जिसे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप से पूरी दुनिया में कई सारे मरीज पीड़ित हैं। उच्च रक्तचाप के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है। अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं लेकिन उच्च रक्तचाप कई बड़ी बीमारियों को जन्म देता है।
- **विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 थीम:** दुनिया भर में कम जागरूकता दर का मुकाबला करने के लिए इस साल की थीम 'अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें' है। इस दिन की शुरुआत द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग (WHL) द्वारा की गई थी, जो स्वयं 85 राष्ट्रीय हाई ब्लड प्रेशर लीग और समाजों के संगठनों के लिए एक समूह है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का इतिहास

- पहली बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2005 में मनाया गया। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई। 2006 से प्रतिवर्ष 17 मई को इसे मनाया जाने लगा।

उच्च रक्तचाप क्या है?

- एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि ये 140/90 या उससे ऊपर ज्यादा है तो ऐसी स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। मोटापा, अव्यवस्थित दिनचर्या, जेनेटिक कारणों से भी लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। रक्तचाप के बढ़ने पर हार्ट पर दबाव पड़ने लगता है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम हाइपरटेंशन है, जो गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक, मनोभ्रंश, क्रोनिक किडनी रोग और दृष्टि हानि का कारण बन सकता है।

हाइपरटेंशन इसलिए है खतरनाक

- हाइपरटेंशन सिर्फ स्वयं तक सीमित नहीं रहता है, धीरे-धीरे उससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। हाइपरटेंशन के मरीज को हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक का खतरा होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सावधानी रखना चाहिए। इससे किडनी के खराब होने एवं अन्य अंगों के खराब होने का खतरा भी बना रहता है।

विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस

- हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। मानव जीवन में संचार का महत्व बहुत अधिक है। संचार के द्वारा ही सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना संचार के इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल नई थीम के साथ वर्ष वर्ल्ड टेलीकम्यूनिकेशन एंड इनफार्मेशन सोसाइटी डे मनाता है।

इस वर्ष की थीम

- इस वर्ष वर्ल्ड टेलीकम्यूनिकेशन एंड इनफार्मेशन सोसाइटी डे 2021 की थीम 'चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को तेज करना' रखी गई है।

दूरसंचार क्या है?

- संचार जो केबल, टेलीग्राफ या प्रसारण द्वारा दूर से किया जाता है, दूरसंचार के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यह संकेतों, संदेशों, शब्दों, लेखन, छवियों और ध्वनियों या किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रसारण है। प्रौद्योगिकी के बिना संचार प्रतिभागियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव नहीं है।

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस (WTISD) का उद्देश्य

- विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के उपयोग की संभावनाओं को पैदा करने में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना, उन्हें समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में लाना और डिजिटल विभाजन को पाटने का एक तरीका बनाना है।

पृष्ठभूमि

- विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस (WTISD) 1969 से हर 17 मई को आईटीयू की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- आईटीयू की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर को चिह्नित करते हुए 17 मई 1969 को

पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया । इसकी स्थापना 1973 में मालागा-टोरेमोलिनोस में प्लेनिपोटेंटरी सम्मेलन द्वारा की गई थी। नवंबर 2005 में, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित करने का आह्वान किया। मार्च 2006 में, महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया कि विश्व सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाएगा। नवंबर 2006 में, तुर्की के अंताल्या में आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस एक साथ मनाने का फैसला किया।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह

- संयुक्त राष्ट्र 17 मई, 2021 और 23 मई, 2021 के बीच 6वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह (Global Road Safety Week) थीम: Streets for Life है तथा थीम की टैगलाइन #Love30 है।

वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। पहला वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह (Global Road Safety Week) 2007 में मनाया गया था। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने और सड़क हादसों को कम करने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य

- वैश्विक एजेंडे पर सड़क सुरक्षा लाना और सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना. जीवन को बचाने के लिए सिद्ध रणनीतियों पर कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों को परिभाषित करें।

दुनिया भर के आंकड़ों पर एक नजर

- सड़क यातायात दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग सड़क हादसो के शिकार होते हैं.
- सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा ने 2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों की वैश्विक संख्या को आधा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

- सड़क यातायात दुर्घटनाओं में अधिकांश देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत खर्च होता है।
- सभी सड़क यातायात मौतों में से आधे से अधिक असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं में से हैं: पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक।

- दुनियाभर के निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सड़कों पर 93 प्रतिशत मौते होती है, भले ही इन देशों में कोरोना के 60 प्रतिशत वाहन हैं।

एक नजर में भारत की तस्वीर

- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के केवल एक प्रतिशत लोग वाहनों के साथ दुर्घटना के शिकार होते हैं, वहीं भारत में सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मृत्यु का हिस्सा 11 प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।
- देश में प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं।
- सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों और चोटों के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। 11 प्रतिशत हिस्सा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का है, हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
- हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। पिछले एक दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख अन्य घायल हुए।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि दुर्घटना लागत 5.96 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.14 प्रतिशत है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की सामाजिक-आर्थिक लागत 1,47,114 करोड़ रुपये है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के 0.77 प्रतिशत के बराबर है।
- व्यक्तिगत स्तर पर सड़क दुर्घटना की चोटें और मौतें एक गंभीर वित्तीय बोझ डालती हैं और पूरे (गैर-गरीब) परिवारों को गरीबी में और पहले से ही गरीबों को कर्ज में धकेल देती हैं।
- मंत्रालय के अनुसार, सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों में से 76.2 प्रतिशत लोग अपनी मुख्य कार्य आयु 18-45 वर्ष के हैं।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) से संबन्धित आंकड़ों को जारी किया है। भारत सरकार ने बताया है कि पीएमजीकेएवाई के तहत 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मई, 2021 के लिए 100 प्रतिशत खाद्यान्न ले लिया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने पीएमजीकेएवाई के तहत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 31.80 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है।

2. प्रमुख बिन्दु

- 17 मई, 2021 तक सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम से 31.80 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उठाया है।
- केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने मई और जून 2021 के लिए पूर्ण आवंटित खाद्यान्न उठा लिया है।
- वहीं 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा ने भी मई 2021 के लिए आवंटित 100 प्रतिशत खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है।
- भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएमजीकेएवाई के तहत समयबद्ध तरीके से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने और वितरित करने के लिए जागरूक किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की लागत और अंतर्राज्यीय परिवहन आदि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी।

3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP)

- कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package-PMGKP) की शुरुआत मार्च 2020 को की गई थी। इसके अंतर्गत तीन योजनाएँ आती हैं-
  - स्वास्थ्य कर्मियों के लिये बीमा योजना
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
  - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

- कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana& PMGKAY) को मार्च 2020 में मंजूरी प्रदान की गई थी।
- दरअसल इस योजना को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package-PMGKP) के एक हिस्से के रूप में लांच किया गया था।
- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (National Food Security Act- NFSA) के तहत प्रदान किये जाने वाले 5 किलो अनुदानित अनाज के अतिरिक्त निशुल्क अनाज प्रदान किया जाता है।
- अतिरिक्त निशुल्क अनाज की यह मात्रा 5 किलोग्राम है।

5. 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act- NFSA)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। पात्र व्यक्ति को चावल/ गेहूं/मोटे अनाज क्रमशः 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के वहनीय मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया जाता है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किया जाता है।

02 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक आयोजित हुई है।

2. मुख्य बिन्दु

- चीन के प्रयासों के चलते हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) की बैठक आयोजित हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चीन ही है।
- यह बैठक वर्चुअल रूप से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सभी 15 सदस्यों (5 स्थाई व 10 अस्थाई) सदस्यों ने भाग लिया है।
- हालांकि इस बैठक में कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं जारी हो सका, किन्तु विभिन्न सदस्यों ने इसमें इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शान्ति की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि वह अपनी पूर्ववत नीति के तहत फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देता है।
- इस बैठक में कई देशों ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में की जा रही सैनिक कार्यवाई का विरोध किया है।

3. भारत का पक्ष

- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति (T S Tirumurti) ने भारत के विचार रखते हुए कहा कि हम दोनों देशों से यथास्थिति में एकतरफा बदलाव न करने की अपील करते हैं, दोनों को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
- सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरुशलम और उसके आसपास में मौजूदा यथास्थिति को एकतरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने की अपील करते हैं।
- टीएस तिरुमूर्ति (T S Tirumurti) ने इजरायल-हमास की लड़ाई के कारण पश्चिमी किनारे (वेस्ट बैंक) में भी हिंसा भड़कने की आशंका जताई है।
- बैठक में तिरमूर्ति ने कहा कि पूर्वी यरुशलम में शुरू हुई गाजा और पश्चिम किनारे के और भागों में भी फैलने की आशंका है।

4. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के बारे में

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) तक विश्व में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत नहीं था। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती थी। स्वयं से सुरक्षा के कई नुकसान थे-
  - देशों के बीच हथियारों की होड़ लगी रहती थी।
  - आपस में सभी एक-दूसरे पर शक करते थे, इससे युद्ध की संभावना बनी रहती थी।
  - प्रथम विश्व युद्ध की भारी तबाही को देखते हुए लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) का सिद्धांत आया, लेकिन लीग ऑफ नेशन्स व्यवहारिक तौर पर कार्य नहीं कर पायी और दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का दंश सहना पड़ा।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा की प्रबल रूप से आवश्यकता महसूस की गयी। सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) का निर्माण हुआ।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाभिक (Nucleus) है।
  - अगर यूएनएससी के कार्य प्रभावित होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि यूएनएससी में सुधारों की बात की जाती है ताकि संयुक्त राष्ट्र जैसी महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्था प्रासंगिक बनी रहे।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महान शक्ति क्लब (Great Power Club) भी कहा जाता है।
  - वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्य बदलते रहते हैं और इनके पास वीटो शक्ति भी नहीं होती है।
  - उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का चुनाव दो वर्षों (वर्ष 2021-22 के च) के लिए हुआ है।

03 हाथियों की मृत्यु से संबन्धित आँकड़ा

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने बताया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है।

2. मुख्य बिन्दु

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के मुताबिक, देश में वर्ष 2009-10 और 2020-21 के बीच पिछले 10 वर्षों में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल 186 हाथियों की मौत हुई है।
- वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, असम में रेलवे पटरियों पर सबसे ज्यादा हाथी (62) हताहत हुए, इसके बाद पश्चिम बंगाल (57) और ओडिशा (27) का स्थान आता है।
- यह स्थिति तब है जब भारत सरकार ने रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति का गठन किया है।
- सरकार के अन्य प्रयासों के बावजूद, देश में हथियों के हताहत होने की लगातार घटनाएँ सामने आ रही हैं। हाल ही में असम राज्य के नौगांव जिले के कोठियाटोली वन क्षेत्र में 18 हाथी मृत पाये गए थे।

3. हाथियों की मृत्यु रोकने के लिए सुझाव

- विशेषज्ञों ने रेल एवं अन्य कारणों से हाथियों की मृत्यु को रोकने हेतु विभिन्न सुझावों को दिया है।
- रेल द्वारा हाथियों की मृत्यु को रोकने हेतु सबसे प्रमुख सुझाव 'पारिस्थितिकी-पुल' (इको-ब्रिज) का निर्माण करना है। अतः सरकार को 'पारिस्थितिकी-पुल' (इको-ब्रिज) के निर्माण पर काफी ध्यान देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ये ब्रिज एक प्रकार के वन्यजीव गलियारे होते हैं, जिन्हें समान वन्यजीव आवासों के दो बड़े क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने वाले वन्यजीव क्रॉसिंग के रूप में भी जाना जाता है।
- वन विभाग के वन्यजीव पर्यवेक्षकों द्वारा रेलवे दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों की नियमित गशत करनी चाहिए।
- तस्करों द्वारा हथियों को हताहत करने से बचाने हेतु सरकार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

4. एशियाई हाथी (Asian Elephants)

- एशियाई हाथी, एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं।
- ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं।
- एशियाई हाथी को आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में एनडैनजर्ड (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- एशियाई हाथी की तीन प्रजातियाँ हैं- भारतीय हाथी, सुमात्राई हाथी और श्रीलंकाई हाथी।

5. भारतीय हाथी

- भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया है।
- भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है।
- फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि (सीएमएस) के 13वें सम्मेलन (कॉप-13) में भारतीय हाथी को भी सीएमएस समझौते की अनुसूची-I में शामिल किया गया है।

6. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था।
- इस अधिनियम का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना है।
- वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

04 जेलों में भीड़भाड़ : एक बारहमासी समस्या

1. चर्चा में क्यों?

- भारत के जेलों में भीड़भाड़ एक बारहमासी समस्या रही है, किन्तु कोरोना महामारी के दौरान यह गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पात्र कैदियों की अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- सुप्रीम कोर्ट ने देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह होना बड़ी समस्या है और यह कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलने का बड़ा कारण हो सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का उद्देश्य जेलों में भीड़भाड़ कम करना तथा कैदियों के जीवन तथा स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करना है।
- पिछले साल कोर्ट ने इस तरह का एक आदेश बहुत पहले ही पारित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देशव्यापी तालाबंदी से पहले ही आया था। अदालत ने तब सभी राज्यों को निवारक कदम उठाने के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन करने का आदेश दिया था ताकि उन कैदियों की श्रेणी निर्धारित की जा सके जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जमानत या पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जेल में कई अधिकारियों के अलावा कई विजिटर्स भी आते हैं। इस वजह से कैदियों को वायरस का संक्रमण लगने की आशंका ज्यादा होती है। बेंच ने यह भी कहा कि जेल कोरोना वायरस के फैलने का कारण बन सकते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में निर्धारित मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके तहत पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं करने के लिए कहा गया था, खासकर उन मामलों में जिनमें जेल की सजा सात साल से कम है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-A

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश के सभी जिलों के अधिकारी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- Cr.P.C) की धारा 436-ए को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए के तहत अगर कोइ कैदी अपने उस कथित अपराध के लिये कानून में निर्धारित सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका हो तो उसे जमानत या निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है।
- हालांकि, यह लाभ उन विचाराधीन कैदियों को नही मिल सकता जिनके खिलाफ किसी ऐसे अपराध में लिप्त होने का आरोप है जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है या फिर कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान किया गया हो।

4. अंडरट्रायल कैदियों की क्षमता से अधिक संख्या

- दिल्ली की तिहाड़ जेल और संभवतः पूरे भारत में लगभग 82% कैदी अंडरट्रायल हैं। देश भर के 19 राज्यों की जेल अपनी 100 फीसदी क्षमता से ज्यादा भरी हैं। इन जेलों में 67.7 फीसदी वो कैदी हैं, जो अंडरट्रायल हैं।
- यानी जिनका केस या तो अभी सुना जा रहा है। या उनके आरोपों की जांच चल रही है। आश्चर्यजनक बात ये है कि एक दशक पहले भी जेलों में 66 फीसदी अंडरट्रायल कैदी बंद थे। पूरे दस साल बाद भी अंडरट्रायल कैदियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है।

5. आगे की राह

- बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोनावायरस की महामारी की वजह से ही शायद देश की जेलों की हालत में सुधार हो जाये और सजायाफ्ता कैदियों की तुलना में कहीं ज्यादा बंद विचाराधीन कैदियों में ज्यादातर की रिहाई हो जाये।
- यदि ऐसा होता है तो इससे छोटे मोटे अपराध के आरोप में बंद हुये आरोपियों को समाज में फिर से पुनर्वास का अवसर ही नहीं मिलेगा बल्कि इससे जेलों पर पड़ रहा आर्थिक बोझ भी कम करने में मदद मिलेगी।

05 ओडिशा के जनजातीय समूहों में कोविड संक्रमण का प्रसार

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में बोंडा और डोंगरिया कोंध जनजातियों सहित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTGs) के बीच संक्रमण फैल गया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- एकांत जीवन शैली के लिए जानी जाने वाली बोंडा जनजाति के 12 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसी तरह, एक अन्य पीवीटीजी समूह डोंगरिया कोंध जनजाति के 23 सदस्यों ने रायगडा के कल्याणसिंहपुर ब्लॉक के परसली पंचायत में वायरल बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है।

3. ओडिशा में जनजातीय समूह

- 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल आदिवासी आबादी में ओडिशा का हिस्सा 9% था। आदिवासी राज्य की आबादी का 22.85 प्रतिशत हैं। अपनी जनजातीय आबादी की संख्या के मामले में, ओडिशा भारत में तीसरे स्थान पर है।
- ओडिशा, देश में सबसे बड़ी और सबसे विविध जनजातीय आबादी में से एक है। ओडिशा में रहने वाले 62 आदिवासी समूहों में से 13 को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है।ओडिशा राज्य में 13 'विशिष्टत: असुरक्षित जनजातीय समूह' (PVTGs) निम्नलिखित हैं-डोंगरिया कोंध (Dungaria Kandha), बोंडा (Bonda), बिरहोर (Birhor), चुक्तिया भुंजिया (Chuktia Bhunjia), दीदई (Didayi), हिल खरिया (Hill Kharia), जुआंग (Juang), कुटिया कोंध (Kutia Kondh), लांजिया सोरा (Lanjia Saora), लोढ़ा (Lodha), मनकीडिया (Mankirdia), पाउड़ी भुइयां (Paudi Bhuyan) और सौरा (Saora)।
- बोंडा ओडिशा के सबसे दक्षिणी जिले मलकानगिरी में समुद्र तल से 3,500 फीट ऊपर ऊंचे इलाकों में रहते हैं। ओडिशा में करीब 6,000 बोंडा हैं। इसी तरह 10,000 डोंगरिया कोंध रायगडा-कालाहांडी सीमा पर नियमगिरि पर्वत पठार पर 112 गांवों में रहते हैं।

4. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- सर्वप्रथम 1973 में ढेबर आयोग द्वारा जनजातीय समूहों में से सर्वाधिक कम विकसित समुदायों के लिए पृथक से "आदिम जनजातीय समूह (primitive tribal group) के नाम से श्रेणीबद्ध किया गया।
- सर्वप्रथम वर्ष 1975 में भारत सरकार द्वारा 52 अनुसूचित जनजातियों PVTGs नामक एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1993 में 23 और अनुसूचित जनजातियों को आदिम जनजातीय समूह (primitive tribals groups) के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
- भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजतियों को विशिष्ट मानदंडों जैसे- कम होती या स्थिर जनसंख्या (declining in population or stagnant population), कम साक्षरता दर (low literacy rate), प्राकृतिक कृषि तकनीक (pre-agriculture technique), आर्थिक पिछड़ापन (economically backwordness) एवं पृथक्करण(पेवसंजपवद) आदि आधार पर चिन्हित किया जाता है।

5. PVTGs हेतु योजनाएं

- PVTGs के विकास संबंधी योजना में 75 चिन्हित PVTGs शामिल हैं। इस योजना में PVTGs के विकास हेतु आवास, भूमि वितरण, भूमि और कृषि विकास आदि पर बल दिया जाता है। यह पूर्णत: केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है।
- नौकरियों और स्वरोजगार के लिए जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना। जनजातीय जनसंख्या के समग्र विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006: यह जनजातीय के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत च्ट्ळे के आवास संबंधी अधिकार का प्रावधान किया गया है।

6. PVTGs से संबन्धित तथ्य

- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पीवीटीजी समूह के लिए निर्दिष्ट उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर देश में वर्तमान में 75 पीवीटीजी समूहों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इसके लिए नोडल एजेंसी भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय ही है।
- ये पीवीटीजी समूह देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में निवास करते हैं।
- राज्यों में सबसे ज्यादा ओडिशा में पीवीटीजी समूह (13) हैं, जबकि राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा में एक-एक पीवीटीजी समूह हैं।
- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी समूह हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं- ग्रेट अण्डमानीज, जारवा, ओंग, सेंटिनलीज, शोम पेन।
- देश में पीवीटीजी की जनसंख्या लगभग 27,68,22 है। 12 पीवीटीजी ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 50 हजार या इससे अधिक है जबकि अन्य समूह की जनसंख्या 1000 या इससे कम है।
- राजस्थान में निवास करने वाले पीवीटीजी 'सहारिया' की जनसंख्या सबसे अधिक '4,50,217' है, जबकि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज और ग्रेट अण्डमानीज की संख्या सबसे कम क्रमश: 39 और 43 है।

06 वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1. सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ (Migration and Development Brief) रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है जिसने प्रेषित धन के रूप में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष (2019) की तुलना में केवल 0.2 प्रतिशत कम है।

2. प्रमुख बिन्दु

- वर्ष 2019 में, भारत को 83.3 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में भारत को प्रेषित धन में केवल 0.2% की गिरावट आई है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषित धन में 17% की कमी के कारण सर्वाधिक गिरावट हुई है।
- पाकिस्तान में, प्रेषण में 17% की वृद्धि हुई। पाकिस्तान के लिए प्रेषण में सबसे बड़ी वृद्धि सऊदी अरब से हुई।
- भारत और चीन के बाद क्रमशः मेक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्राँस तथा बांग्लादेश का स्थान है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (68 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से प्रेषित धन का बहिर्वाह सर्वाधिक था, इसके बाद यूएई (43 बिलियन), सऊदी अरब(34.5 बिलियन), स्विट्जरलैंड(27.9 बिलियन), जर्मनी (22 बिलियन)तथा चीन (18 बिलियन)का स्थान है।

3. प्रेषित धन या रेमिटेंस क्या है?

- प्रेषण विकासशील देशों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है।
- जब एक प्रवासी अपने मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। विकासशील देशों में इस धनराशी का निर्धनता उन्मूलन में काफी महत्व होता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में विश्व के कई विकासशील देशों में रेमिटेंस विदेशों से होने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।

4. धन प्रेषण से लाभ

- धन प्रेषण से परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

5. रेमिटेंस में गिरावट के नुकसान

- दुनिया के सारे प्रवासी भारतीय बहुत धनी नहीं हैं। अधिकांश देशों में इनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से विभिन्न खाड़ी देशों में लाखों कुशल-अकुशल भारतीय श्रमिक इस बात से त्रस्त हैं कि वहां पर इन्हें न्यूनतम वेतन और जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे मे धन प्रेषण मे कमी से उनके परिवारों को विभिन्न परेशानियों से गुजरना पड़ता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के साथ ही देशों में संरक्षणवादी विचारधारा को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे आने वाले दिनों में प्रवासी कामगारों के लिये रोजगार के अवसरों में गिरावट देखी जा सकती है।

07 आर्कटिक क्षेत्र में सैन्यीकरण के खिलाफ अमेरिका

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र में सैन्यीकरण से बचना चाहता है, हालांकि रूस ने आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में "आर्कटिक काउंसिल" की मंत्रिस्तरीय बैठक में इस रणनीतिक क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों का बचाव किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के वर्षों में रूस के आर्कटिक क्षेत्र को एक रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया है और सैन्य बुनियादी ढांचे और खनिज निष्कर्षण में निवेश का आदेश दिया है, जिससे आर्कटिक परिषद के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ गया है।
- अगर आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि होती है तो संभव है कि यह क्षेत्र अशांत हो सकता है जिससे इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण और स्थाई भविष्य के साझा लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

3. आर्कटिक क्षेत्र

- आर्कटिक क्षेत्र, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र है तथा इस धरती के लगभग 1/6 भाग पर फैला है (तकरीबन रूस, चीन और भारत के आकार को एक साथ मिलाकर)।

4. आर्कटिक परिषद के बारे में

- आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी फोरम है जो आर्कटिक सरकारों और आर्कटिक के स्वदेशी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करता हैं।
- आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों, आर्कटिक के स्थानीय समुदायों तथा अन्य आर्कटिक वासियों के साथ साझा आर्कटिक मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देता है।
- आर्कटिक परिषद की स्थापना साल 1996 में ओटावा घोषणापत्र के द्वारा हुई है।
- आर्कटिक परिषद विशेष रूप से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर आर्कटिक देशों, क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों और अन्य निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देती है।

5. आर्कटिक परिषद के सदस्य देश

- कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका, आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं।
- पर्यवेक्षक सदस्यः जर्मनी, अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति, नीदरलैंड, पोलैंड, उत्तरी मंच, यूनाइटेड किंगडम, भारत चीन इटली, जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापूर।
- गैर सरकारी सदस्यः यूएनडीपी, आईयूसीएन, रेडक्रॉस, नार्डिक परिषद्, यूएनईसी।

6. संरचना

- सचिवालय और मंत्रिस्तरीय बैठक आर्कटिक परिषद के मुख्य अंग हैं। सचिवालय का कोई स्थायी कार्यालय नहीं है तथा इसकी अध्यक्षता और स्थान प्रत्येक दो वर्षों पर सदस्यों के मध्य आवर्तित होते हैं। मंत्रिस्तरीय बैठकों के निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं। यह बैठक प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है।

7. गतिविधियां

- आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा करने के लिये एक आकटिक पर्यावरणीय संरक्षण रणनीति (एईपीएस) को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त पांच और कार्यक्रम विकसित किये गये, जो इस प्रकार हैं-आर्कटिक विश्लेषण और आकलन योजना (एएमएपी); आर्कटिक सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण (पीएएमई); आपातकाल, निवारण तैयारी और प्रतिक्रिया (ईपीपीआर); आर्कटिक जीव, जंतु और पादप संरक्षण (सीएएफएफ), तथा; सतत विकास एवं उपयोग (एसडीयू)।
- आर्कटिक परिषद आर्कटिक क्षेत्र को हमारे भूमंडल के लिये एक शीघ्र पर्यावरणीय चेतावनी प्रणाली के रूप में परिभाषित करती है और यह आशा रखती है कि संपूर्ण विश्व इस बात का अनुभव करेगा कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अधोगति का एकमात्र निदान पर्यावरण के मुद्दे पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग है।

8. आर्कटिक क्षेत्र में चुनौतियाँ

- जलवायु परिवर्तन तथा इसकी वजह से आर्कटिक आइस कैप का तेजी से पिघलना सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो आर्कटिक पर वैश्विक संदर्श को फिर से परिभाषित कर रही है। वर्तमान वैज्ञानिक अभिमत से पता चलता है कि 2030 के दशक तक आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी के महीने लगभग आइस फ्री हो सकते हैं जिससे न केवल पार्श्विक राज्यों के लिए अपितु समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी प्रचुर अवसरों के साथ-साथ चुनौतियों के द्वार खुलेंगे।
- यद्यपि आर्कटिक आयल एवं गैस भंडारों, समुद्री सजीव संसाधनों जिनका दोहन नहीं किया गया है तथा प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाले छोटे पोत परिवहन मार्ग आदि के आकर्षण से इन्कार नहीं किया जा सकता है, फिर भी देशज समुदायों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा वैश्विक तापन में वृद्धि पर पिघलते आर्कटिक आइस कैप के प्रतिकूल प्रभावों से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग

प्र. निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत में निर्वाचन आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है
2. इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
4. मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 2 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

2. तियानवेन-1

प्र. हाल ही में चर्चित तियानवेन-1के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. लगभग सात महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद चीन के 'तियानवेन-1' मिशन ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है।
2. 'तियानवेन-1' मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था।
3. इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर का नाम 'झुरोंग' है।
4. मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने वाले श्झुरोंग' रोवर का भार लगभग 240 किलोग्राम है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) उपर्युक्त सभी
(D) 1, 2 और 3

ANS: (C)

3. स्किंक की नई प्रजाति

प्र. हाल ही में पश्चिमी घाट (Western Ghats) से स्किंक (Skink) की नई प्रजाति मिली हैके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. स्किंक (Skink) की इस नई प्रजाति को 'सबडॉलूसेप्स नीलगिरिएन्सिस' (Subdolusepsnilgiriensis) नाम दिया गया है।
2. स्किंक की इस नई प्रजाति के नाम में 'नीलगिरिएन्सिस' शब्द नीलगिरि की पहाड़ियों के कारण दिया गया है।
3. स्किंक की इस नई प्रजाति का शरीर लगभग 7 सेमी पतला है और यह रेतीले भूरे (sandy brown) रंग की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

4. जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

प्र. जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समावेशी, कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और आश्रम स्कूल जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है।
3. इस प्रयास द्वारा भारत में जनजातीय छात्रों को डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से आवश्यक कौशल मुहैया कराया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1 , 2 और 3

Ans: (C)

5. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

प्र. थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है।
2. इसमें मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को सबसे ज्यादा भार दिया जाता है।
3. इसे भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी किया जाता है।
4. थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) उपर्युक्त सभी

(D) केवल 1 और 2

Ans: (C)

6. मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपियाँ

प्र. मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपियाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मंगोलियाई बौद्धों द्वारा इसका काफी सम्मान किया जाता है तथा वे मंदिरों में कंजुर की पूजा करते हैं
2. मंगोलिया में लगभग प्रत्येक बौद्ध मठ में कंजुर को रखा जाता है
3. कंजुर की शास्त्रीय भाषा चीनी है
4. मंगोलियाई कंजुर मंगोलिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ माना जाता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 3 और 4

(C) केवल 1, 2 और 4

(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (C)

7. चीन की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर पर

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 1970 के दशक में चीन ने एक बच्चे की नीति लागू की थी
2. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2030 तक चीन की आबादी बढ़ती रहेगी और अपने चरम पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद उसमें कमी होनी शुरू होगी

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सहीं है/हैं?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

8. एकीकृत बागवानी विकास मिशन

प्र. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
2. वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 तक बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 9% और 14% तक बढ़ा है।
3. कुल परिव्यय का भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के मामले में 90% योगदान करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त मे से कोई नहीं

Ans: (C)

9. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई 2021 से सितंबर 2021 तक छह किस्तों में जारी करेगी।
2. इन बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित बैंकों, डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये की जाएगी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सहीं है/हैं?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

10. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311

प्र. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों, यानी लोक सेवा अधिकारियों पर लागू होते हैं।
2. अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षात्मक उपाय सिविल सेवकों के साथ-साथ रक्षाकर्मियों पर भी लागू होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

11. ताउते चक्रवात

प्र. हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते (Cyclone Tauktae) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसका नाम म्यांमार ने दिया था।
2. यह बर्मी शब्द है, जिसका मतलब है - अधिक शोर करने वाली छिपकली।
3. चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत (डब्ल्यूएमओ/ईएससीएपी) पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन (पीटीसी) द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

12. लॉक डाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी

प्र. लॉक डाउन के दौरान बाल विवाह में बढ़ोतरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. कोविड 19 महामारी से पहले, भारत उन देशों में से एक था, जहां बाल विवाह के खिलाफ अभियान चरम पर था।
2. अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक चाइल्डलाइन की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कुल 2,180 बाल विवाह के मामले सामने आए हैं।
3. पिछले साल दिसंबर में 1,598 शिकायतों में से 365 इस श्रेणी से संबंधित थीं। अन्य शिकायतें अवैध रूप से गोद लेने, बाल तस्करी और बाल श्रम से लेकर जुड़ीं थीं।
4. सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट (Save the Children report) कहती है कि अगले पांच साल में कोरोना महामारी के कारण 2.5 मिलियन लड़कियों की शादी जल्दी हो सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

Ans: (D)

13. बीमा बांस

प्र. बीमा बांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. उन्हें हर फसल चक्र के बाद दोबारा उगाने की आवश्यकता नहीं होती है।
2. वे ऊतक संस्कृति के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो इसे विभिन्न मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के ढलने की सुविधा प्रदान करते हैं।
3. बांस का कैलोरी मान कोयले के लगभग बराबर है। इस प्रकार, सीमेंट उद्योगों ने इस बांस को अपने बॉयलरों के लिए खरीदना शुरू कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

14. मेक्सिको में मिली 'बातूनी' डायनासोर की नई नस्ल

प्र. मेक्सिको में मिली 'बातूनी' डायनासोर की नई नस्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यह डायनासोर शाकाहारी था और संभवत: शांतिपूर्ण लेकिन बातूनी था।
2. वह परभक्षियों को डरा कर भगाने के लिए या प्रजनन संबंधी उद्देश्यों के लिए तेज आवाजें निकालते थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

15. रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ

प्र. रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेकेमीस स्क्रिप्टा एलिगेंस (Trachemys Sscripta Elegans) है।
2. पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला यह कछुआ मूल रूप से अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में पाया जाता है।
3. इस कछुए के कानों के समीप लाल धारियां पायी जाती हैं तथा यह किसी भी सतह से पानी में जल्दी से सरक जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ पड़ा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) उपर्युक्त सभी

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01

03

05

01 मंगोलियाई कंजुर पांडुलिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, साथ ही यह भी बताइये कि ये पांडुलिपियाँ किस प्रकार ज्ञान और शोध के रूप में कार्य करती हैं?

02 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) क्या है? यह किस प्रकार किसानों कि आय दोगुनी करने में सहायक है? परीक्षण कीजिये।

03 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित क्यों है। मूल्यांकन कीजिये।

04 क्या धारा 311 (2) के तहत बर्खास्तगी को सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जा सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

05 चक्रवात की उत्पत्ति को समझाते हुए इससे निपटने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाइए।

06 हाल ही में बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बाल विवाह की घटनाओं को देखकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह संबंधी मामलों में हो रही बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया है। भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिये।

07 वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बीमा बांस सबसे अच्छा कार्बन सिंक (carbon sink) है। परीक्षण कीजिये।

08 रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ (Red-Eared Slider Turtle) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल निकायों की जैव विविधता के लिये किस प्रकार एक बड़ा खतरा बन सकता है? चर्चा कीजिये।

09 निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम की मांग न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को किस प्रकार प्रभावी बनाएगी? मूल्यांकन कीजिये।

10 जनजातीय स्कूलों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार आदिवासी शिक्षा में बदलाव का वाहक बनेगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

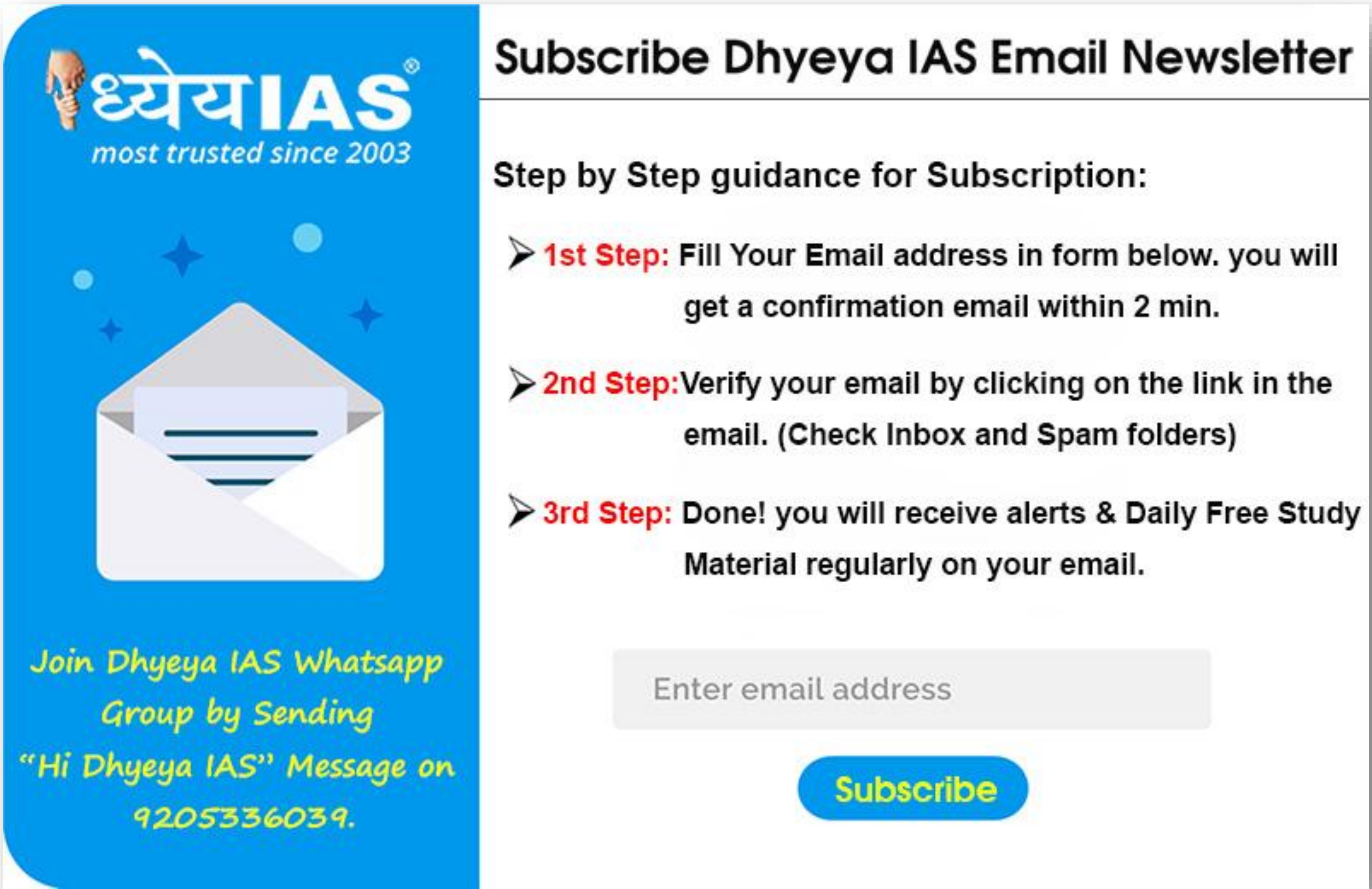

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com